RNI NO.: UPHIN/2010/32733

ग्राम भारती

कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता और पंचायतीराज का पाक्षिक

वर्ष 11 अंक 10 लखनऊ, मंगलवार, 01 सितंबर 2020 मूल्य 5 रुपये पृष्ठ 8

यूरिया संकट, बेहाल किसान

ग्राम भारती ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद का गंभीर संकट है। पूरब से पश्चिम तक हर जिले में किसान यूरिया की कमी से बेहाल है। खरीफ की फसलों खासकर धान के लिए यह समय खाद लगाने का है। ऐसे में पूरे प्रदेश में एक साथ यूरिया का संकट खड़ा हो जाने से किसानों का दिन और रात खाद की दुकानों, सहकारी समितियों के चक्कर लगा-लगा कर बीत रहा है किन्तु उस जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है किन्तु हकीकत एकदम उलट है, प्रदेश में या तो यूरिया मांग के अनुरूप जिलों को भेजा ही नहीं गया अथवा उसकी भारी पैमाने पर जमाखोरी हुई है। यही वजह है कि किसानों को ब्लैक में और ऊंचे दामों पर यूरिया

खरीदना पड़ रहा है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार यूरिया की कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। हालात इतने खराब हैं कि किसान सुबह सहकारी समिति पर यूरिया के लाइन लगाते हैं और खाद मिलने का नम्बर आने से पहले ही स्टाक खत्म होने की सूचना दे दी जाती है। मायूस किसान पूरे पूरे दिन लाइन में लगने के बाद वापस लौटते हैं और अगले दिन फिर इसी तरह लाइन में लग जाते हैं। लेकिन, उन्हें आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल रही है। खेती के लिए यह समय खरीफ फसलों में यूरिया खाद लगाने का है। विशेष रूप से धान के लिए यूरिया की जरूरत है।

मुरादाबाद के बिलारी विकास खण्ड के ग्राम भूड़ा निवासी प्रगतिशील किसान राजवीर सिंह बताते हैं कि क्षेत्र में यूरिया की किल्लत है। किसानों को महंगे दामों पर ब्लैक में यूरिया खरीदनी पड़ रही है। वह जरूरत से काफी कम मात्रा में मिल पा रही है।

भीतर पढ़ें

खेत-खलिहान

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

♦प्रधान सराफत हुसैन से बातचीत पृष्ठ चार पर

♦यूरिया संकट पृष्ठ चार और पांच पर

♦एनसीडीसी का चैनल लांच पृष्ठ सात पांच पर

♦भारत में सबसे ज्यादा हैं जैविक किसान

किसान को उत्पादक के साथ एक उद्यमी बनाने का लक्ष्य: प्रमं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों को वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने देश में कृषि क्षेत्र किये गए रिफार्म और कृषि क्षेत्र में उच्चतम और गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये सिर्फ खाद्यान्न तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की बात है। ये देश के अलग-अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है।

कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेंगे तो बड़े स्तर पर गांव में

और गांव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफार्म ये सरकार लगातार कर रही है, कई और किए गए हैं।

बंदिशों में जकड़ने वाली व्यवस्था से किसान को बाहर लाने की कोशिश

भारत में किसान को बंदिशों में जकड़ने वाली कानूनी व्यवस्थाएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून, इन सबमें बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में मंडियों से बाहर भी जहां उसको ज्यादा दाम मिलते हैं, वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की सुविधा मिले, इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। इस फंड के माध्यम से हमारे कृषि उत्पादक संघ, हमारे एफपीओ अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक ढांचा भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी, इन सबको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते बनेंगे। ---शेष पृष्ठ सात पर

ग्राम प्रधान

सराफत हुसैन

खुद की कमाई से करते हैं गांव के जरूरतमंदों की मदद

जनता की आकांक्षाओं पर शत प्रतिशत खरा उतरने के कारण ही मैं विगत 15 वर्ष से प्रधान पद पर आसीन हूं और इसके पूर्व में मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा। मेरा बीस वर्ष का पंचायत की राजनीति का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। मैंनें अपने विपक्षी प्रत्याशियों और मतदाताओं को कभी कोई कष्ट नहीं होने दिया। मैं अपनी पंचायत के नागरिकों को 24 घंटे सहायता देने के लिए तत्पर रहता हूॅ। मैंने अपनी जनता की पंचायत के धन से नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई के धन से जरूरत मंद लोगों की सहायता की है। अल्लाह ने मुझे आज इस लायक बनाया है कि मैं अपनी जनता की सेवा करने लायक बना हूं तो मैं सब की सेवा अवश्य करूंगा। यह बात सीतापुर जनपद के विकास खंड खैराबाद की ग्राम पंचायत इलसिया ग्रन्ट के प्रधान ***सराफत हुसैन*** *ने एक साक्षात्कार में कही। प्रस्तुत है ग्राम भारती के प्रतिनिधि* ***आलोक कुमार बाजपेयी*** *की प्रधान सराफत हुसेन से बातचीत के कुछ प्रमुख अंशः संपादक।*

प्रश्नः- प्रधान जी आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

उत्तरः- मैं सिर्फ इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हूँ। बी.काम अन्तिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाया था, जिसके कारण स्नातक नहीं हो सका।

प्रश्नः- आप पंचायत की राजनीति में क्यों आए ?

उत्तरः- लोग राजनीति में आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन मैंने आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को आगे बढ़ाने की सोचता हूँ। जिसका परिणाम यह है कि मैं विगत 15 वर्षों से प्रधान हूँ।

■ राजनीति सेवा है, लेकिन बदलते समय में आज लोगों ने इसे व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिसका दुष्प्रभाव यह है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है।

■ लोग राजनीति में आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं, लेकिन मैंने आगे बढ़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को आगे बढ़ाने की सोचता हूँ। जिसका परिणाम यह है कि मैं विगत 15 वर्षों से प्रधान हूँ।

प्रश्नः- पंचायत की राजनीति में आपने कब से प्रवेश किया ?

उत्तरः- सर्वप्रथम मैं वर्ष 2000 से 2005 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, उसके पश्चात2005 से 2010 तक प्रधान चुना गया। वर्ष 2010 से 2015 तक मेरी पत्नी श्रीमती रेशमा बानों प्रधान निर्वाचित हुई। उसके बाद वर्ष 2015 से आज तक मैं पुनः प्रधान हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं इस बार मैं विकास खंड खैराबाद की सभी ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक मतों से विजयी प्रधान हूँ।

प्रश्नः- राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं और क्या मानते हैं ?

घर-परिवार व मित्रों के सहयोग के बिना कोई समाज सेवा पूर्ण हो ही नहीं सकती है

उत्तरः- राजनीति सेवा है, लेकिन बदलते समय में आज लोगों ने इसे व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लिया है। जिसका दुष्प्रभाव यह है कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है।

प्रश्नः- इस बार आप अपनी पंचायत में कौन-कौन से कार्य नहीं करा पाये ?

उत्तरः- इस बार सिर्फ मनरेगा से संचालित कार्य नहीं करा पाया क्योंकि मेरी पंचायत के लोग शहर में कार्य करना अधिक पसन्द करते हैं। शहर में कार्य करने का एक मात्र कारण यह है कि वहाँ अधिक मजदूरी मिलती है, जबकि मनरेगा के तहत कम मजदूरी मिलती है। मेरी पंचायत में लगभग 250 मजदूर पंजीकृत हैं।

प्रश्नः- इस कार्यकाल में आपकी पंचायत में कराये गए उल्लेखनीय कार्य क्या-क्या हैं ?

उत्तरः- मैंने प्रधानमंत्री/इन्दिरा आवास योजना के तहत लगभग 150 आवास बनवाये हैं। सीसी रोड व इंण्टरलाकिंग से गलियों व नालियों का निर्माण करवाया है। वर्तमान में कच्ची रोड़ का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा बृद्धावस्था पेंशन 100, विकलांग पेंशन 11, विधावा पेंशन 50 स्वीकृत करायी हैं तथा 100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये हैं।

प्रश्नः- आपकी ग्राम पंचायत में कौन-कौन से गॉव सम्मिलित हैं ? व वर्गवार कितने मतदाता हैं ?

उत्तरः- मेरी ग्राम पंचायत में कुल 5 गॉव सम्मिलित हैं, जिनमें इलसिया, रामपुर, मढ़िया, किशुनकोट, करतालपुर हैं। मेरी ग्राम पंचायत में कुल 2800 मतदाता हैं। जिनमें लगभग दो प्रतिशत सामान्य वर्ग के तथा अनुसूचित जाति व पिछडे वर्ग के लगभग बराबर-बराबर मतदाता हैं।

"मेरी पंचायत के कई लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था लेकिन समाज कल्याण विभाग से उन्हें पेंशन नहीं मिल पायी, वो लोग कॉफी परेशान थे। जिसके चलते मैंने अपने पास से 22 हजार रुपए पात्र वृद्धों में वितरित कराया है।"

प्रश्नः- वर्तमान में आपको कितने प्रतिशत मतदाता पसन्द करते हैं ?

उत्तरः- वर्तमान में मुझे मेरी ग्राम पंचायत के लगभग 80 प्रतिशत मतदाता पसन्द करते हैं। इसका आंकलन इसी आधार पर किया जा सकता है कि वर्ष 2000 से अब तक 4 चुनाव मैंने लड़े हैं जिनमें लगातार मेरे पक्ष में मतदान प्रतिशत बढ़ता ही रहा है। पहली बार क्षेत्र पंचायत के चुनाव में 175 से विजयी हुए। उसके पश्चात प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें 375 मतों से विजयी हुए। उसके बाद मेरी बेगम श्रीमती रेशमा बानो प्रधान पद की उम्मीदवार रहीं जिन्हें 660 मतों से विजय प्राप्त हुई।

पंचायत प्रतिनिधि साक्षात्कार

उसके बाद पुनः मुझे प्रधान पद का चुनाव लड़ने का मौका मिला जिसमें 880 मतों से विजय प्राप्त हुई। जो मेरे विकास खंड का सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रधान का खिताब दिलाया।

प्रश्नः- आपका धनार्जन का क्या जरिया है ? जिस पर आपका और आपके परिवार का भरण-पोषण आधारित है।

उत्तरः- मैंने टेलीफोन की ठेकेदारी से अपना कार्य शुरू किया था। उसकेपश्चातमैंने पीडब्ल्यूडी, आरईएस व नगर पालिका में ठेकेदारी का कार्य शुरु किया। परन्तु वर्तमान में मेरा ठेकेदार के रूप में पंजीकरण नहीं है। मैं दूसरे के पंजीकरण पर कार्य करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास 50 बीघा कृषि योग्य भूमि है। इसके अलावा मेरी एक डेयरी है जिसमें करीब 25 भैंस हैं। मेरे पास तीन ट्रैक्टर व एक जेसीबी मशीन है। इस सभी से मैं धनार्जन करता हूॅ।

प्रश्नः- प्रधान जी आपके घर-परिवार के लोग आपके कार्य में कोई सहयोग करते हैं ?

उत्तरः- जी, बिल्कुल बिना घर-परिवार व मित्रों के सहयोग के कोई समाज सेवा पूर्ण हो ही नहीं सकती है। जब कोई व्यक्ति अपने घर को ही नहीं सम्भाल पायेगा तो क्षेत्र की जनता को क्या संभालेगा ? मुझे सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। मेरे तीन पुत्र हैं जो सभी शिक्षार्थी है। जिनमें बड़ा बेटा शिक्षा ग्रहण करने हेतु जर्मनी जा रहा है। मैं घर से पंचायत के सभी लोगों से काफी प्रशन्न हूॅ। मेरे प्रतिद्वन्दी प्रत्याशियों से भी मेरे काफी प्रगाढ़ सम्बन्ध हैं। जिनसे प्रतिदिन मुलाकात व विकास कार्य के मुद्दों पर मंत्रणा भी होती है। सभी लोग मुझे काफी सहयोग कर रहे हैं।

प्रश्नः- प्रधान नहीं बल्कि बतौर मानवता आपने कोई कार्य किया है ?

उत्तरः- मैं यहां पर यह नहीं कह सकता हूॅ कि मैंने मानवता के नाते कोई कार्य किया है या नहीं ! लेकिन अभी मेरी पंचायत के कई लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था लेकिन समाज कल्याण विभाग से उन्हें पेंशन नहीं मिल पायी, वो लोग कॉफी परेशान थे। जिसके चलते मैंने अपने पास से 22 हजार रुपए पात्र वृद्धों में वितरित कराया है।

प्रधानमंत्रीआवास योजना के तहत लगभग 150 आवास बनवाये हैं। सीसी रोड व इंण्टरलाकिंग से गलियों व नालियों का निर्माण करवाया है। वर्तमान में कच्ची रोड़ का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा बृद्धावस्था पेंशन 100, विकलांग पेंशन 11, विधावा पेंशन 50 स्वीकृत करायी हैं तथा 100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये हैं।

ग्राम भारती

पाक्षिक

वर्ष 11, अंक 10

01 से 15 सितंबर, 2020

(कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता एवं पंचायत का पाक्षिक)

संपादक

सर्वेश कुमार सिंह

संपादकीय कार्यालय

204, दूसरा तल, प्रिंस काम्पलेक्स

हजरतगंज, लखनऊ-226001

Phone & Mob. No.

9453272129 ,

Whatsapp No.

9140624166

E mail: grambhartilko@gmail.com

पृष्ठ 8, मूल्य 5 रूपये

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः सर्वेश कुमार सिंह

प्रिंटरः माडर्न प्रिन्टर्स,10 घसियारी मण्डी, कैसरबाग,लखनऊ लखनऊ 226001

अभिनंदनीय किसान

संपादकीय

भारत के किसानों का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाना चाहिए। उस उपलब्धि के लिए जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और विशषज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह उपलब्धि है घनघोर कोरोना संकट काल में भी 3.4 प्रतिशत विकास दर हासिल करना। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोरोना की बेरहम और क्रूर मार से पूरा विश्व त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कर रहा है। इस वायरस ने जहां मानव जाति के जीवन पर गंभीर संकट पैदा किया है। वहीं, समाज जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है और अस्त-व्यस्त कर दिया है। कोरोना ने सबसे बुरा प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर डाला है। इसके दुष्प्रभावों के कारण समूची अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उद्योग, व्यापार और रोजगार सभी प्रभावित हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है। यहां का आर्थिक तंत्र भी तीन महीने के लंबे लाकडाउन से अछूता नहीं रहा। उद्योग बंद हो गए, उत्पादन ठप हो गया। यातायात साधन बंद होने से आपूर्ति प्रभावित हो गई। इसका असर यह हुआ कि देश के विकास का पहिया एकदम थम गया। अर्थव्यवस्था की विकास दर शून्य से भी नीचे चली गई। हालत इतनी खराब हो गई कि वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही यानि कि अप्रैल से मई के बीच विकास दर शून्य से नीचे चली गई और यह -23.9 प्रतिशत पहुंच गई। यह गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुई है। वहीं दूसरी ओर संतोष की बात यह रही कि देश की कृषि विकास दर इस समान अवधि में 3.4 प्रतिशत रही। यह दर हासिल करके भारत के कृषि क्षेत्र ने यह साबित कर दिया कि देश को संकट से उबारने में केवल किसान ही सक्षम है। इसमें वह अदृश्य जिजिविषा है जो कोरोना वायरस के प्रकोप क्या किसी भी आपदा को पराजित कर अजेय रह सकती है। यह किसानों की हिम्मत और परिश्रम का प्रतिफल हह्य। जब अप्रैल, मई और जून में पूरा देश लॉकडाउन में था, तब भी किसान खतरे मोल लेकर खेती-किसानी के काम मे जुटा था। देश के अर्थशास्त्री और नीति निर्धारक अब भी समझ लें कि भारत की असली आर्थिक ताकत कहाँ है। यह उपलब्धि इसलिए संभव हो सकी है कि भारत के किसानों का अपना एक व्यवहारिक और पारंपरिक ज्ञान और भावना प्रधान तंत्र है, जोकि पीढी दर पीढ़ी चलता है। इसमें कठोर परिश्रम, खेत के प्रति मृातभाव और पशुओं के प्रति पारिवारिक भाव समाहित है। ये ऐसी भावनाएं जोकि किसान को किसी भी संकट या आपदा में भी इनकी रक्षा करने, समर्पण और त्याग के लिए प्रेरित और ऊर्जावान बनाता है। इस भाव के कारण ही किसान को कोरोना का भय उसके खेतऔर पशुप्रेम से विचलित नहीं कर सका। परिणाम आया कि कोरोना के भय से जब देश का अभजात्य वर्ग और शहरी जनजीवन घरों में दुबका था तो किसान खेतों में था, खलिहानों में था। पशुओं की सेवा और पालन के लिए तत्पर था। इसी का परिणाम है कि भारत की कृषि विकास दर उन्नति कर सकी हह्य। किसान के इस भाव और उपलब्धि के लिए अन्नदाता का अभिनंदन है।

कैसे बढ़ेगा कृषि उपज निर्यात

आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने के लिए कृषि क्षेत्र का आत्मनिर्भर होना जरुरी है। इसके लिएकीमती विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ ही कृषि निर्यात को बढावा दिया जाना आवश्यक है।

विश्व व्यापार संगठन केआंकड़ों के अनुसार 2017 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात और आयात का हिस्सा क्रमशः 2.27 प्रतिशतऔर1.90 प्रतिशत था। कोविड महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कठिन समय में भी, भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात जारी रखते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखा कि विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में किसी तरह की बाधा नहीं आए। मार्च - जून 2020 की अवधि में देश से 25552.7 करोड़ रूपए की कृषि वस्तुओं का निर्यात हुआ जो कि 2019 की इसी अवधि में हुए 20734.8 करोड़ रूपए के निर्यात की तुलना में 23.24 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017-18 में भारत का कृषि निर्यात देश के कृषि जीडीपी का जहां 9.4 प्रतिशत था वहीं 2018-19 में यह 9.9 प्रतिशत हो गया जबकि भारत के कृषि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि आयात 5.7 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशतरह गया जो निर्यात योग्य अधिशेष को दर्शाता है। इसके साथ ही देश की कृषि उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो गई है।

आजादी के बाद से कृषि निर्यात के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। वर्ष 1950-51 में, भारत का कृषि निर्यात लगभग149 करोड़ रुपये था जो 2019-20 में बढ़कर 2.53 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। पिछले 15 वर्षों में लगभग सभी कृषि वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादनके मामले में शीर्ष पर होने के बावजूद कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में देश बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों की सूची में स्थान नहीं पा सका है। उदाहरण के रूप में भारत, दुनिया में गेहूं उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन निर्यात के मामले में यह 34 वें स्थान पर है। इसी तरह सब्जियों के उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद निर्यात के मामले में यह 14 वें स्थान पर है। जहां तक फलों का मामला है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इस क्षेत्र में भी यह निर्यात के मामले में 23वें स्थान पर है।

नयी निर्यात नीति में मुख्य रूप से आरोग्य और स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थों, पोषण युक्त आहार तथा इस संदर्भ मेंब्रांड इंडिया को बाकायदा एक अभियान के रूप में बढ़ावा देने की तैयारी की गई है और इसके माध्यम से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में पैठ बनाने की योजना है। इसके लिए विशेष रूप से खाड़ी देशों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वर्तमान में खाड़ी देशों में आयात की जाने वाली वस्तुओं में भारत की भागीदारी महज 10-12 प्रतिशत है। एक उत्पाद बाजार मैट्रिक्स को ताकत के उत्पादों की सूची से युक्त किया गया है जिसे नई भौगोलिक और विस्तारित बाजारों की सूची में विस्तारित किया जा सकता है जिन्हें नए उत्पादों के साथ पेश किया जा सकता है।

किसान एक एकड़ भूमि के,यूरिया खरीदी 1195 बोरी!!

यूरिया खाद का अभूतपूर्व संकट है। हर जिले से यूरिया नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। किन्तु वहीं दूसरी ओर इस यूरिया संकट का एक पहलू यह भी है कि किसानों ने ही बड़े पैमाने पर यूरिया का भंडारण किया है। अथवा वे कालाबाजारी करने वालों के सहयोगी बन रहे हैं। सीतापुर में यूरिया संकट की जब हमारे संवाददाता आलोक कुमार वाजपेयी ने पड़ताल की तो यह सच उजागर हुआ । जिसे पांच बोरी खाद चाहिए उसने एक हजार बोरी खरीद लीं।

सीतापुर। आज के समय में कालाबाजारी करने में कोई पीछे रहना नहीं पसन्द कर रहा है। बस पीछे वही रह गया जिसे मौका नहीं मिला! अभी तक सुनने में आता था कि विभागों में काफी बड़े स्तर पर घोटाला किया जा रहा है लेकिन अब तो कुछ किसान भी पीछे नहीं हैं। कुछ दिनों पहले प्रपत्रों की छानबीन में सामने आया कि एक किसान के पास मात्र एक एकड़ जमीन ही है और यूरिया खाद उसने 1195 बोरी खरीद डाली! यह वाकया देख अधिकारियों का माथा ठनक गया। जब जॉच शुरु हुई तो पता चला कि ऐसे करीब 20 किसान हैं जो तकरीबन 9737 बोरी यूरिया खरीद चुके हैं। हॉलांकि किसानों का अपना तर्क यह है कि उन्होंनें काफी जमीन ठेके पर ले रखी है जिस कारण उन्हें इतनी यूरिया की बोरी क्रय करने की आवश्यकता महसूस हुई। कृषि अधिकारी अखिलानन्द पाण्डेय बताते हैं कि इसमें किसानों को आगे कर खाद माफिया लाभ कमाने में लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संदेह के घेरे में आये किसानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि खाद का उपभोग कितनी जमीन में किया जाना है व उनके पास जमीन कितनी है उसके प्रपत्र मांगे गये हैं। कितनी खाद क्रय की गयी और कहां से क्रय की गयी है तथा खाद का भंडारण कहॉ किया गया है। यदि किसी किसान ने नोटिस का समय पर जवाब नहीं दिया तो उसे खाद घोटाले में संलिप्त माना जायेगा।

इस प्रकरण का भंडाफोड़ तब हुआ जब कृषि विभाग ने यूरिया बोरी की शासन से मॉग कर दी। तब शासन में बैठे अधिकारियों ने जमीन के सापेक्ष भेजी गयी कुल यूरिया बोरियों की पीओएस मशीन की बिक्री फीडिंग से मिलान किया जिसमें आशंका व्यक्त की गयी कि सीतापुर में यूरिया खाद की काफी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। जॉच में पाया गया कि जिन किसानों को पॉच बोरी यूरिया से अधिक नहीं मिलनी चाहिए थी उन्हें 320 से लेकर 1195 बोरियां तक यूरिया बेच दी गयी है। ऐसे किसानों को विभाग चिन्हित कर नोटिस भेजते हुए जांच प्रारम्भ कर दी है। जिला कृषि अधिकारी अखिलानन्द पांण्डेय ने बताया है कि पीओएस मशीन द्वारा अंगूठा लगाकर एक अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक जिन 20 किसानों ने जमकर यूरिया खरीदी है। उनमें सबसे पहला नाम उमाकांत शुक्ला का आया है। इन्होंने 1194 बोरी यूरिया खरीदी है। दूसरे स्थान पर अभय प्रताप मौर्य हैं, जिन्होंने 811 बोरी क्रय की हैं। वहीं तीसरे स्थान पर कुमकुम कपूर हैं। इन्होनें 643 बोरी यूरिया क्रय की है। इसी प्रकार अनुज कश्यप 614, रविशंकर तिवारी 486, रमाकांत शुक्ला 480, मो0 मोनीश रजा 455, सुभाष चंद 440, अर्चना देवी 432, दुर्गेश कुमार 431, सुभाष वर्मा 407, सुमित वर्मा 400, कुलदीप कुमार ने 396, राममूर्ति 377, शेषराम 375, ओमप्रकाश 356, पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा 340, नूर आलम 325 व नितिन कुमार ने 320 बोरी यूरिया क्रय की है। कृषि विभाग उक्त सभी किसानों को नोटिस जारी कर कार्रवाई प्रारम्भ कर चुका है। अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ छापे 75 खाद विक्रेताओं के यहां डाले गये जहां पर 11 दुकानों में गड़बड़ी पाते हुए सभी 11 दुकानों के लाइसेंस निलम्बित कर दिये गये और अभी कार्रवाई जारी है।

जिले में 23 अगस्त 2020 को छापेमारी में कालाबाजारी करने वाले उर्वरक विक्रेता आखिरकार अधिकारियों के हत्थे चढ़ ही गये। जिसके चलते 3 दुकानदारों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बतातें चलें कि यूरिया बिक्री में जिले के अन्दर खाद माफियाओं द्वारा भारी गड़बड़ी की गयी है। किसानों के आधार कार्ड पर फर्जी तरीके से खाद निकाल ली गयी है और उसे ब्लैक कर ली गयी है। इसकी जानकारी जब कृषि विभाग को हुई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा छापामार कार्यवाही की गयी। जिला कृषि अधिकारी अखिलांनन्द पाण्डेय तथा कृषि उप निदेशक अरविन्द मोहन मिश्र द्वारा की गयी संयुक्त कार्यवाही से खाद विक्रेताओं में हड़कम्प मचा हुआ है। सबसे पहले सर्वशक्तिमान कृषक सेवा केन्द्र कुंवरपुर गड्डी के यहॉ छापेमारी की कार्यवाही की गयी। इस प्रतिष्ठान पर यूरिया नहीं थी लेकिन इनके द्वारा एक कमरे में अवैध भंडारण कर निर्धारित दर अधिक मूल्य पर यूरिया बेची जा रही थी। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचे जाने एवं स्टाक प्रदर्शित न किए जाने से कारण विक्रेता रमेश चन्द्र यादव पुत्र सुन्दर लाल यादव निवासी ग्राम मुड़ेरवा दौलतपुर बेहमा विकास खंण्ड कसमंण्डा थाना सिधौली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। वहीं शिव मार्केटिंग कम्पनी भंडिया विकास खंण्ड कसमंण्डा के यहां छापेमारी की गयी तो उनके यहां भी यूरिया की मात्रा शून्य पायी गयी। लेकिन इनके द्वारा 19 व 20 अगस्त को 2000 बोरी यूरिया क्रय की गयी थी जिसे 1-2 दिन में ही बेच दिया गया, लेकिन पीओएस मशीन में कोई बिक्री नहीं दिखी। जिसके चलते खाद विक्रेता अनिल कुमार जायसवाल पुत्र श्रीराम जायसवाल के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। वहीं साधन सहकारी समिति चुनका के सचिव शिव प्रकाश अवस्थी पर निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने की शिकायत पर सचिव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। जिन्हें पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। कृषि अधिकारी ने बताया कि फुटकर विक्रेताओं की पीओएस मशीन यह दशार्ती है कि यूरिया स्टाक में है लेकिन वास्तव में है नहीं। पड़ताल में कुछ किसानों का कहना है कि हमनें खाद खरीदी ही नहीं है लेकिन उनके नाम पर किसी ने खाद खरीदी है वहीं कुछ किसान कहते हैं कि मैंने काफी जमींन ठेके पर ले रखी है जिसमें मुझे खाद का उपयोग करना है। लेकिन विभागीय जॉच अभी जारी है। अभी कितनी परतें खुलनी शेष हैं यह आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन किसानों की समस्या को देखते हुए शासन ने 7500 मीट्रिक टन खाद जननद को बिक्री हेतु उपलब्ध करादी है। जिसका अधिकारियों की देख-रेख में पीओएस मशीन से बिक्री का शुभारम्भ भी करा दिया गया है।

बिलारी क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत, किसान परेशान, प्रशासन उदासीन

– राजवीर सिंह –

बिलारी (मुरादाबाद)। क्षेत्र में यूरिया की जबरदस्त किल्लत है। गन्ना, धान और अन्य खरीफ फसलों के लिए इस समय यूरिया की जरुरत है। लेकिन, यूरिया की कमी के चलते कालाबाजारी चरम पर है। किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक यूरिया नहीं मिल रही है। जिन लोगों को यूरिया मिल पाती है वह भी अधिक दाम देने को मजबूर हैं। निजी दुकानदारों द्वारा खुलेआम यूरिया को निर्धारित दर से अधिक पर बेचा जा रहा है। लेकिन, किसान की समस्या के समाधान की किसी को चिंता नहीं है। दुकानों पर लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं, किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। दुकानदार अपनी मनमानी कर कर यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं।सुबह से ही सहकारी सुबह होते ही क्षेत्र की सहकारी समितियों पर यूरिया लेने के लिए किसानों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ में कुछ को यूरिया मिल जाता है कुछ ऐसे ही वापस चले जाते हैं। प्राइवेट दुकानदारों में भी दुकानदार यूरिया की कलाबाजरी कर रहे हैं। दुकानदार किसान से दुकान में यूरिया नहीं होने की बात कह कर भगा देते हैं और बाद में लगभग 400 रुपये का ब्लैक में बेच देते हैं। प्रशासनिक अमला आने पर दुकान बंद कर देते हैं और फिर बाद में खोल लेते हैं।

यूरिया की कालाबाजारी से त्रस्त हैं किसान

यूरिया की कालाबाजारी: किसान आक्रोशित

जरूरत से ज्यादा खाद खरीदने पर चंदौली में नौ किसानों को नोटिस

- श्रीप्रकाश यादव -

चन्दौली । जनपद में किसानों को इस समय यूरिया खाद के लिये काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ।इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ज्ञापन दिया जा रहा है ,जबकि सूबे के मुखिया का दावा है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया है।

उधर किसानों की माने तो जनपद में लगभग 80 सहकारी समितियां व दर्जनों प्राइवेट लाइसेंसी दुकानें संचालित हैं मगर अधिकांश सहकारी समितियों पर खाद की किल्लत बनी हुई है । जहाँ कहीं गाहे बगाहे यूरिया की खेप आ भी रही है तो अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से 267 रुपये बोरी की यूरिया 270 से 275 में बेची जा रही है।ओवर रेटिंग व कालाबाजारी से किसान त्रस्त हैं। ऐसे में किसान प्राइवेट दुकानों से महंगी दर पर खाद लेने

त्रिभुवन सिंह
किसान नेता चंदौली

को मजबूर हैं। जनपद में खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर विभागीय अधिकारी एलर्ट हैं ।सहकारी समितियों व प्राइवेट दुकानों से अधिक मात्रा में कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद खाद लेने वालो पर उपनिदेशक कृषि राजीव भारती ने कुल नौ सचिवों , बीस किसानों , दो दुकानों को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब तीन दिनों के अंदर देना होगा।यूरिया की किल्लत को देखते हुए सपा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर , पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू , सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आवाज उठायी गई । जनपद में जोत की भूमि कम होने के बावजूद नौ समितियों व दो दुकानों से ज्यादा खाद उठायी गयी है ।इस शिकायत पर जिलाधिकारी चन्दौली नवनीत सिंह चहल द्वारा विगत 17 अगस्त 2020 को जिला पिछड़ा कल्याण वर्ग के अधिकारी को जांच करने हेतु नामित किया था । जिसमें कालाबाजारी की शिकायत सही पायी गई । तत्पश्चात आरोपित नौ समितियों व दो दुकानों व बीस किसानों को नोटिस भेज दी गयी थी।इस सम्बंध में धानापुर ब्लॉक के निदिलपुर समिति के अध्यक्ष राम अनुज सिंह , प्रमुख समाज सेवी व किसान त्रिभवन सिंह , रमेश चंद पांडेय , शिवबदन यादव , आदि लोगों का आरोप है कि सहकारी समितियों व प्राइवेट दुकानों पर खुलेआम ओवर रेटिंग में खाद की कालाबाजारी की जा रही है शिकायत के बावजूद सम्बन्धित अधिकारी मौन हैं । खाद की किल्लत से आम किसान परेशान है ।

क्या कहते है अधिकारी

कृषि उपनिदेशक जनपद चन्दौली राजीव भारती कहते हैं कि जनपद में खाद की कोई किल्लत नहीं है। कोई भी निर्धारित रेट से अधिक कीमत लेता है तो इसकी तत्काल सूचना दीजिये। अभी तक जनपद में मिली शिकायत पर कुल नौ सहकारी समितियों , दो दुकानों व बीस किसानों को कालाबाजारी के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। ये तीन दिन के भीतर कार्यालय में स्पष्टीकरण दें।

सहकारी समितियों व प्राइवेट दुकानों से अधिक मात्रा में कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद खाद लेने वालों पर उपनिदेशक कृषि राजीव भारती ने कुल नौ सचिवों , बीस किसानों , दो दुकानों को नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब तीन दिनों के अंदर देना होगा। यूरिया की किल्लत को देखते हुए सपा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर , पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू , सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आवाज उठायी गई

नौगढ़ मे सेटिंग के आधार पर ओवररेटिंग पर बांटी गई यूरिया

नौगढ़ (चंदौली)। तहसील क्षेत्र नौगढ़ के स्थानीय थाना के पास नौगढ़ क्षेत्रीय सहकारी समिति पर जिला मुख्यालय से यूरिया खाद की खेप पहुंचने से पहले ही कोआपरेटिव सचिव ने लोगों से सेटिंग कर ली थी।

यूरिया उन्हीं किसानों को दी गई जिनके साथ पहले सेटिंग थी। वहीं मुख्य रूप से खास बात यह भी रही कि देश में चल रही कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी भी धज्जियां उड़ाई गईं।

मौके पर निरीक्षण के दौरान देखा गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंस या मास्क लगाए नहीं दिखा।

खाद की ओवररेटिंग भी की गई 267.50 रुपये की जगह 270 रुपये लिया गया। सहकारी समिति पर उपस्थित लोगों का कहना था कि हम लोगों का आधार कार्ड बहुत पहले जमा किया गया था और हम लोगो को युरिया खाद नही मिली लेकिन बात कुछ लोग जो हम लोगों के बाद आए और अपना आधार कार्ड कोआपरेटिव सचिव को दिए सचिव ने उन लोगों को यूरिया कि खाद दे दिया। जबकि कुछ समय बाद हम लोगो का आधार कार्ड देकर वापस भेज दिया गया।

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मकान में रहने के लिए विवश गीता देवी

सकलडीहा (चन्दौली)। भारी बरसात और आंधी तूफान ने गरीबों के आशियाने उजाड़ दिये हैं। कई लोगों के घर वर्षा और आंधी तूफान की भेट चढ़ गए।इससे वे बेघर हो गए हैं।इससे उन्हें खुले आसामान के नीचे जीवन गुजारना पड़ रहा है। ऐसी ही घटना विगत दिनों यहां हुई तेज बरसात में हुई जब आंधी के साथ हुई बरसात के कारण गुरुवार को सकलडीहा विकासखंड क्षेत्र के ताजपुर गांव निवासी लालचंद राम पुत्र मग्गन राम का रिहायशी मकान भरभरा कर गिर पड़ा। घर में चार बच्चों के साथ रह रही रामचंद्र की पत्नी गीता देवी बाल बाल बच गई,घर का छत जमींदोज हो जाने के कारण उसमें रखे गए

भारी बरसात और आंधी ने उजाड़ दिये गरीबों के आशियाने

खाद्यान्न सहित कपड़े नष्ट हो गए। इस बात को लेकर गीता देवी अपने बच्चों के साथ रोती रही जिसे देख ग्रामीणों ने खाने के लिए अनाज एवं कपड़े तो दे दिया, परंतु बरसात के कारण खुले में जिंदगी बीता पाना उसके लिए कठिन बन गया है। घटना के बाबत ग्राम प्रधान अमित सिंह ने तहसीलदार को अवगत कराते हुए बताया कि मजदूरी कर जीवन व्यतीत करने वाले इस परिवार को तत्काल आवासीय सुविधा मुहैया कराया जाए।

गरीबी और लाचारी से परेशान लालचंद राम अपनी पत्नी गीता देवी के साथ चार छोटे छोटे बच्चों की परवरिश करने के लिए मजदूरी करने का कार्य करता है। पीड़ित रामचंद्र ने जिला प्रशासन से प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करने का गुहार लगायी है।

गन्ना सीजन 20-21 के लिए केन्द्र ने निर्धारित किया 285 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 19 अगस्त को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुसार गन्ना सीजन 2020-21 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारण को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार गन्ना सीजन 2020-21 के लिये एफआरपी 10 प्रतिशत की रिकवरी के आधार पर 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.85 रुपये का प्रीमियम प्रदान करने तथा प्रत्येक रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की कमी पर एफआरपी में 2.85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमी करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी चीनी मिलों के लिए है जिनकी रिकवरी 10 प्रतिशत से कम लेकिन 9.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि ऐसी चीनी मिलों के लिए जिनकी रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे कम है एफआरपी 270.75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया हैगन्ना उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इस नजरिये से एफआरपी का निर्धारण हितकर होगा ।गन्ने का ह्यएफआरपीह्ल गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत निर्धारित होता है। इसे देशभर में समान रूप से लागू किया गया है।

भारत में सबसे ज्यादा हैं जैविक खेती करने वाले किसान

जैविक खेती के विकास की गाथा न केवल भारत में,बल्कि विश्व स्तर पर भी बढ़ती मांग की बदौलत अब पूरी तरह से हमारे सामने है। कोविड महामारी से त्रस्त दुनिया में स्वास्थ्यवर्धक एवं सुरक्षित भोजन की मांग पहले से ही निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः इस सुखद स्थिति को बयां करने का यह बिल्कुल उपयुक्त समय है कि किस तरह से यह हमारे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए फायदे का सौदा है।

सिक्किम जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला राज्य

भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर वन है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से नौवें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया। यही नहीं, त्रिपुरा एवं उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ठीक इसी तरह के लक्ष्य तय किए हैं। पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है और यहां रसायनों की खपत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी कम है।इसी तरह आदिवासी या जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों को अपनी जैविक गाथा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जैविक खेती अपनाने में किसानों की सहायता करने और प्रीमियम मूल्यों की बदौलत पारिश्रमिक बढ़ाने के उद्देश्य से दो विशेष कार्यक्रम यथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडी) और परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था, ताकि रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही कृषि-निर्यात नीति 2018 के तहत दिए गए विशेष जोर के बलबूते भारत वैश्विक जैविक बाजारों में एक प्रमुख देश के रूप में उभर कर सामने आ सकता है।

भारत से जैविक निर्यात मुख्यतः अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल और दालों का होता रहा है जो वर्ष 2018-19 में हुए 5151 करोड़ रुपये के कुल जैविक निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करने में काफी मददगार साबित हुए थे। असम, मिजोरम, मणिपुर एवं नगालैंड से ब्रिटेन, अमेरिका, स्वाजीलैंड और इटली को निर्यात करने की जो सामान्य शुरूआत हुई है उसने कुल मात्रा को बढ़ाकर और नए गंतव्यों तक विस्तार करके अपनी क्षमता बखूबी साबित कर दी है। दरअसल, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ने से ही यह संभव हो पा रहा है।

प्रमाणीकरण ग्राहकों में विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से जैविक उत्पाद का एक महत्वपूर्ण अवयव है।पीकेवीवाई और एमओवीसीडी दोनों ही सहभागितापूर्ण गारंटी प्रणाली (पीजीएस) और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं जो क्रमशः घरेलू एवं निर्यात बाजारों को लक्षित कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य पदार्थ) नियमन, 2017 दरअसल एनपीओपी और पीजीएस के मानकों पर आधारित हैं। प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पाद की जैविक प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए संबंधित उत्पाद पर एफएसएसएआई, जैविक भारत/पीजीएस ऑर्गेनिक इंडिया के लोगो को अवश्य ढूंढ़ना चाहिए। जैविक बनने जा रहे रसायन मुक्त उत्पाद को पीजीएस ग्रीन दिया जाता है जिसमें 3 साल लगते हैं।

जैविक खेती में जुटे हैं 160 एफपीओ

पीकेवीवाई के तहत लगभग 40,000 क्लस्टरों की सहायता की जा रही है जिनके तहत लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। एमओवीसीडी लगभग 80,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले 160 एफपीओ को अपने दायरे में लाया है। इन क्लस्टरों को टिकाऊ बनाने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अब से अनुबंध कृषि मोड में बाजार की अगुवाई में उत्पादन शुरू किया जाए, ताकि उपज के लिए एक तैयार बाजार हो और आवश्यकता पड़ने पर उद्योग जगत को भी पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित गुणवत्ता वाली उपज मिल सके। इसे फाइटो एक्सट्रैक्ट उद्योगों सहित थोक खरीदारों के साथ सही मायनों में आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्वाधिक क्षमता वाली जिंसों या वस्तुओं में अदरक, हल्दी, काले चावल, मसाले, पोषक तत्व वाले अनाज, अनानास, औषधीय पौधे, कूटू (एक प्रकार का अनाज), बांस के अंकुर, इत्यादि शामिल हैं। मेघालय से मदर डेयरी के लिए, मणिपुर से रेवंत फूड्स और बिग बास्केट सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से आपूर्ति शुरू हो गई है। किसान समूहों द्वारा आरडब्ल्यूए में बाजार स्थापित करने और सीधे तौर पर बेचने के उदाहरण बड़ी तेजी से महाराष्ट्र और कर्नाटक में सामान्य होते जा रहे हैं, जहां के शहरी लोगों द्वारा ताजा जैविक उत्पादों को धड़ल्ले से खरीदा जा रहा है और किसानों को बिना बिचौलियों के बेहतर मूल्य मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए समूहकों (एग्रीगेटर) की मौजूदगी आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए बाजार की अगुवाई में एक जिला - एक उत्पाद की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तरह बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों में और भी अधिक क्लस्टरों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि वहां जैविक खाद्य पदार्थों की मांग बहुत अधिक होगी।

जब महामारी का प्रकोप भारत में बढ़ा तब गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों को हासिल करना देश के लिए उतनी ही प्राथमिकता पर था जितना कि स्वास्थ्य। मंडियों में भीड़ कम करने के लिए प्रत्यक्ष विपणन का समर्थन करने वाली जो एडवाइजरी राज्यों को दी गई उसे ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने आदेश जारी किए और कानूनों में संशोधन किए जिससे किसानों के लिए बाजार के विकल्प खुल रहे हैं। रसद (लॉजिस्टिक्स) एवं नियमित बाजारों तक पहुंच में व्यवधान और मांग में कमी से जूझते हुए कई राज्यों एवं क्लस्टरों ने नवाचार किया और इस संकट को एक अवसर में बदल दिया। कोहिमा के ग्रीन कारवां ने सब्जियों, हस्तशिल्प और हथकरघों के लिए नगालैंड के सभी गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बाजार संपर्क बनाए। महाराष्ट्र में एफपीओ द्वारा फलों एवं सब्जियों की ऑनलाइन बिक्री की गई और पंजाब में विशेष रूप से डिजाइन की गई इलेक्ट्रिक वैन से ग्राहकों को घरों पर डिलीवरी की गई। मणिपुर ऑर्गेनिक एजेंसी (एमओएमए) ने उपज एकत्र करने और इम्फाल में संजेंथोंग एवं चिंगमेरियोंग स्थित दो जैविक थोक केंद्रों तक ढुलाई के लिए एमओवीसीडी के सभी 15 एफपीसी को एकजुट किया, ताकि उपभोक्ताओं को आगे डिलीवरी की जा सके।

कृषि उत्पादों के लिए ई-कामर्स प्लेटफार्म

किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों से सीधे जोड़ने के लिए जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है। महामारी के दौरान डिजिटल प्रौद्योगिकी का बड़े पह्यमाने पर उपयोग किए जाने की सख्त आवश्यकता महसूस की गई है और यह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है क्योंकि इससे सूचना साझा करने की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर ही यात्रा, लॉजिस्टिक्स इत्यादि पर होने वाले खर्चों में बचत होगी।

दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबिनार ने फील्ड या संबंधित क्षेत्र में कई और लोगों से संपर्क किए जाने को संभव बना दिया है, जिससे उनके कार्यों में कोई विशेष व्यवधान भी नहीं होता है और जो भौतिक बैठकों में कतई संभव नहीं था। पूर्वोत्तर राज्यों ने आईसीएआर द्वारा विकसित एकीकृत जैविक खेती मॉडलों पर आयोजित एक वेबिनार में भी भाग लिया जिसका उद्देश्य उत्पादकता एवं एकीकृत पोषक तत्व बढ़ाना एवं कीट प्रबंधन करना और इस तरह से किसानों की आय बढ़ाना है। कंपनियों के समक्ष मौजूद समस्याओं को समझने और राज्यों एवं क्लस्टरों को आवश्यक सहारा देने की जिम्मेदारी संभालने वाली क्षेत्रीय परिषदों के साथ बातचीत को मजबूती प्रदान करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं और इस प्रक्रिया में किसानों/किसान समूहों से सीधी खरीद के लिए नई साझेदारियां की जा रही हैं।

भारत में प्राकृतिक खेती कोई नई अवधारणा नहीं है, जिस पर अमल करते हुए किसान पुरातन समय से ही रसायनों का उपयोग किए बिना ही मुख्यतः जैविक अवशेषों, गाय के गोबर, खाद, इत्यादि पर निर्भर रहते हुए अपनी जमीन पर खेती करते रहे हैं। मिट्टी, पानी, सूक्ष्म जीवाणुओं एवं अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि जैसे तत्वों के एकीकरण वाली जैविक खेती में अंतर्निहित अवधारणा दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए सही नुस्खा है, जिन पर भोजन और कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल की लगातार बढ़ती आवश्यकता के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है।

यह सतत विकास लक्ष्य 2 के अनुरूप भी है जिसमें भूखमरी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने एवं पोषण में सुधार करने और सतत कृषि को बढ़ावा देने के लक्ष्य रखे गए हैं।

भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर वन है और जैविक खेती के रकबे की दृष्टि से नौवें स्थान पर है। भारत से जै विक निर्यात मुख्यतः अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधों, चावल व दालों का होता है। किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों से सीधे जोड़ने के लिए जैविक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है।

एनसीडीसी का चैनल 'सहकार कॉपट्यूब' लांच

-पीआईबी समाचार-

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहकार कॉपट्यूब चह्यनल का शुभारम्भ किया। एनसीडीसी ने वनस्टॉप चह्यनल के रूप में अपना यह चह्यनल शुरू किया हह्य,जो शुरूआत में हिंदी और 18 राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में रहेगा। श्री तोमर ने राज्यों के लिए ह्यसहकारी समितियों के गठन और पंजीकरणह्ल से संबंधित मार्गदर्शक वीडियो भी जारी किए।इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सहकारिता हमारी संस्कृति की आत्मा हह्य। उन्होंने सहकारिता से नई पीढ़ी के भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि नए चह्यनल जह्यसी पहल से इस दिशा में जागरूकता बढ़ेगी। सहकारिता के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे।

श्री तोमर ने कहा कि जिस तरह परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हुए किसी उद्देश्य के लिए काम करते हह्यं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती हह्य, उसी तरह सहकारिता के माध्यम से समूह में काम करने से निश्चित ही प्रगति होती हह्य। श्री तोमर ने एनसीडीसी की प्रगति की तारीफ करते हुए कहा कि उसने एपेक्स सांविधिक संस्था के रूप में अभी तक सहकारी संस्थाओं को 1,54,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी हह्य और कुल संवितरण का 83 प्रतिशत (98 हजार करोड़ रुपये) अकेले पिछले 6 वर्षों में ही किया हह्य।सहकारिता क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा हुआ हह्य, जो इस चह्यनल के माध्यम से और आगे बढ़ सकेगा। श्री तोमर ने उम्मीद जताई कि नए चह्यनल पर सहकारिता को लेकर जागरूकता का प्रसार होगा और सहकारी समितियों के गठन के साथ ही नए प्रोजेक्ट बनाने आदि के बारे में भी मार्गदर्शन मिलेगा। चह्यनल पर पूरी प्रक्रिया बताए जाने से कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। ज्यादा से ज्यादा युवा सहकारिता से जुड़ेंगे तो रोजगार का सृजन होगा और इसका लाभ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। तकनीक के उपयोग से समय व श्रम दोनों की बचत होगी। युवाओं का खेती की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, पढ़े-लिखे युवा खेती-किसानी से जुड़ेंगे तो कृषि क्षेत्र के साथ ही देश की भी तरक्की होगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोर कृषि क्षेत्र के साथ ही सहकारिता को भी बढ़ावा देने पर हह्य। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दस हजार नए एफपीओ की योजना से भी सहकारिता को बल मिलेगा। भारत सरकार की अनेक योजनाएं हह्यं, जो कृषि क्षेत्र को बल देने वाली हह्यं। इस क्षेत्र में व्यापक सुधार हो रहे हह्यं। इनका उद्देश्य कृषि, बागवानी एवं सम्बद्ध क्षेत्र तथा कृषि बुनियादी ढांचे के विकास, लघु- खाद्य उद्यमों, मूल्य श्रृंखलाओं व मत्स्य पालन एवं पशु पालन, औषधीय व हर्बल पौधों, मधुमक्खी पालन तथा ऑपरेशन ग्रीन के विभिन्न अंगों में विविध प्रकार के सुधार एवं उपाय तथा विभिन्न गतिविधियों एवं सेवाओं को मजबूत बनाना हह्य। केन्द्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए भी पह्यकेज घोषित किए हह्यं, जिनके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को आकार दिया जाना हह्य। ये सब जमीन पर उतरे और एफपीओ की भूमिका सार्थक हो, किसानों की आय बढ़े, उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, किसान ही प्रोसेसिंग, लेबलिंग व पह्यकिंग कर स्वयं अपनी उपज बेच सकें तो निश्चित रूप से उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और आय बढ़ेगी। इस दृष्टि से पह्यकेज बहुत महत्वपूर्ण हह्य, नए चह्यनल से भी इस दिशा में फायदा होगा।

यू-ट्यूब प्लेटफार्म पर चलने वाले, सहकार कॉपट्यूब चह्यनल की शुरूआत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, म ा ह ट ा प्रदेश,बिहार,छत्तीसगढ़,झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, गुजरात, पंजाब एवं कर्नाटक के मार्गदर्शक वीडियो के साथ की गई हह्य। एनसीडीसी के इन-हॉउस डिजाइन स्टूडियो ने विभिन्न राज्यों के लिए विविध भाषाओं में ये वीडियो तह्यार किए हह्यं। कार्यक्रम में एनसीडीसी के एमडी श्री संदीप कुमार नायक ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया।

रिसर्च को कैंपस से फार्म तक पहुंचाएंगे: नरेन्द्र मोदी

पृष्ठ एक का शेष....

आज बीज से लेकर बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का, आधुनिक रिसर्च के फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। छह साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, आज तीन-तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश में कार्यरत हैं। इसके अलावा तीन और राष्ट्रीय संस्थान झारखंड, असम, और बिहार के मोतीहारी में इनकी भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र-छात्राओं को नए मौके तो देंगे ही, स्थानीय किसानों तक टेक्नोलॉजी के लाभ पहुंचाने में भी, उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेंगे।

अभी देश में सोलर पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार गए बीज, माइक्रोइरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए, खासतौर पर बुन्देलखंड के किसानों को इससे जोड़ने के लिए आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 6 साल से ये निरंतर कोशिश की जा रही है रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो, गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। अब कैंपस से लेकर फील्ड तक एक्सपर्ट्स के, जानकारों के इस नेटवर्क को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया जाना जरूरी है। इसमें आपके विश्विद्यालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कृषि से जुड़ी शिक्षा को स्कूल स्तर पर लेजाना भी आवश्यक हह्य। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि केविषय को शामिल किया जाए। इससे दो लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार-कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे।

बुंदेलखंड के एक ओर बेतवा बहती है और दूसरी और केन नदी बहती है। उत्तर दिशामें माँ यमुना जी हैं। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि इन नदियों के पानी का पूरा लाभ, पूरे क्षेत्र को नहीं मिल पाता है।इस स्थिति को बदलने के लिए भी केंद्र सरकार निरंतर प्रयासकर रही है। केन बेतवा नदी लिंक परियोजना में इस क्षेत्र के भाग्य को बदलने की बहुततताकत है। इस दिशा में हम दोनों राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं, काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब बुंदेलखंड को पर्याप्त जल मिलेगा तो यहांजीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब वीरोंकी ये भूमि, झांसी और इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरबनाने के लिए एक बड़ा क्षेत्र विकसित हो जाएगा।

ग्राम भारती पाक्षिक के लिए स्मामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सर्वेश कुमार सिंह द्वारा माडर्न प्रिन्टर्स, 10 घसियारी मण्डी, कैसरबाग,लखनऊ से मुद्रित एवं 103-117, प्रथम तल, प्रिंस काम्पलेक्स हजरतगंज, लखनऊ 226001 से प्रकाशित
फोनः 9453272129
व्हाट्सएपः 9140624166
ई-मेल
grambhartilko@gmail.com

कृषि क्षेत्र में स्टार्ट अप्स पर सालाना 37 हजार करोड़ खर्च

देश भर में 24 आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इंक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) नियुक्त किए गए हैं। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं-

1. एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन: दो माह की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह वजीफे के साथ। वित्तीय, तकनीकी, आईपी मुद्दों आदि पर मेंटरशिप प्रदान की जाती है।

2. आर-एबीआई इनक्यूबेट्स की सीड स्टेज फंडिंग: 25 लाख रुपये तक की फंडिंग (85% अनुदान और 15% अंशदान इंक्यूबेट से)।

3. एग्रीप्रेन्योर्स की आइडिया/प्री-सीड स्टेज फंडिंग : 5 लाख रुपए तक की फंडिंग (90% अनुदान और 10% योगदान इन्क्यूबेट से)।

संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने और विभिन्न चरणों के माध्यम से चयन की कठोर प्रक्रिया अपना कर और दो महीने के प्रशिक्षण के आधार पर, अनुदान-सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किए जाने वाले स्टार्ट-अप्स की अंतिम सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। तकनीकी, वित्त, बौद्धिक संपदा, सांविधिक अनुपालन मुद्दों आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। माइलस्टोन और समयसीमा की निगरानी के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को मेंटरशिप प्रदान करना कार्यक्रम का हिस्सा है कुछ स्टार्ट-अप्स जिन्हें इन्क्यूबेट किया जा रहा है,

निम्नलिखित समाधान प्रस्तुत करते हैं। इनमें प्रमुख हैं-

एक्टिक्स एनीमल हैल्थ टेक्नोलॉजीज :

इसे वेट्ज के नाम से जाना जाता है, यह वेटरनरी डॉक्टरों का एक नेटवर्क है, जो ग्राहकों यानि पशु मालिकों को रियल टाइम टेली कंसल्टेशन और डोरस्टेप विजिट के माध्यम से तत्काल संपर्क प्रदान करता है।

एसएनएल इनोवेशन्स:-- इनोफार्म्स खेत से ग्राहक तक, एक वर्ष तक के भंडार और उपयोग करने की पूर्ण क्षमता के साथ, फलों और सब्जियों को लुगदी में परिवर्तित करने के लिए इन-हाउस विकसित मोनोब्लॉक फल प्रसंस्करण मंच (ऑन-व्हील्स) का उपयोग करके, सीधे खेतों में संसाधित फलों और सब्जियों की लुगदी प्रदान करता है।

ईएफ पॉलिमर :

इसके द्वारा किसानों के लिए पानी की कमी के संकट का समाधान करने के उद्देश्य से एक पर्यावरण अनुकूल जल प्रतिधारण बहुलक विकसित किया गया हद्य। इस स्टार्ट-अप ने मिट्टी में पानी को अवशोषित करने, इसे लंबे समय तक बनाए रखने और आवश्यकतानुसार फसलों को आपूर्ति करने के लिए डिजाइन किया गया एक सुपर शोषक बहुलक बनाया है।

जिन स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है उनमें से कई स्टार्ट-अप्स ऐसे हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं जैसे 'ए2पी एनर्जी सॉल्यूशन' करती हैं। एक ओर यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न करता है और दूसरी ओर ए2पी एकत्रित किए गए बायोमास को ऊर्जा छर्रों, हरे कोयले और जैव तेल जैसे भविष्य के सामान्य जैव ईंधनों में परिवर्तित करता है।

क्यारी इनोवेशन,

मानव और वन्यजीव संघर्ष को भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कम करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रेपेलिट सिस्टम (एएनआईडीईआरएस) नामक एक नवीन उत्पाद बनाया है। यह उपकरण एक मशीनीकृत बिजूका (खेतों में चिडिंया भगाने के लिए लगाया गया पुतला) की तरह काम करता है जो जानवरों की घुसपैठ से खेतों की रक्षा कर सकता है।

एगेसमैर्टिक टेक्नोलॉजीज, के पास सटीक सिंचाई और रोग प्रबंधन द्वारा फसल उपज में सुधार लाने की एक दृष्टि है जिसमें वह एआई, आईओटी और कंप्यूटर का उपयोग करके एक डेटा संचालित दृष्टिकोण अपनाता है। उनके उत्पाद क्रॉपलिटिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधान का एक संयोजन है जो सिंचाई के लिए एक सटीक मॉडल बनाने के लिए डेटा को कार्रवाई योग्य जानकारी में परिवर्तित करने के लिए ग्राउंड सेंसर डेटा और सैटेलाइट इमेजरी को एकीकृत करता है।

उपर्युक्त 6 स्टार्ट-अप्स के अलावा, खेती पारिस्थितिकी प्रणाली में सुधार लाने और घरेलू कृषि आय को बढ़ाने के लिए अभिनव समाधानों के साथ कई और भी हैं।

कुल मिलाकर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कुल 346 स्टार्ट-अप्स को इस चरण में 36 करोड़ 71 लाख 75 हजार रुपये की राशि के साथ वित्त पोषित किया जा रहा है। यह फंड किस्तों में जारी किए जाएंगे।

इन स्टार्ट-अप्स को भारत भर में फैले 29 कृषि व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (केपीएस और आरएबीआइ) में दो महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इन स्टार्ट-अप्स के द्वारा युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए अवसर प्रदान करके आय बढ़ाने में योगदान देंगे।

(स्रोत: पीआईबी)

कृषि विभाग ने 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुना

- राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हह्यदराबाद,
- राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) जयपुर,
- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा, नई दिल्ली,
- कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक और
- असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम

कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इन स्टार्ट अप्स से सरकार गांवों की तस्वीर को बदल देना चाहती है। इसके लिए सालाना लगभग 37 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से धन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन, आम किसान और ग्रामीण युवाओ, उद्यमियों को योजनाओं की पर्याप्त जानकारी ही नहीं है। सरकार की ओर से इन योजनाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। इसलिए योजनाएं कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित होकर रह गई हैं। हम यहां इन स्टार्ट अप्स और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। ताकि गांव के अधिक से अधिक युवा और शिक्षित किसान योजनाओं का लाभ उठा सकें। समस्त जानकारी प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की वेबसाइट से ली गई है। **संपादक**

स्टार्ट-अप्स से गांव की तस्वीर बदलना चाहती है सरकार

नई दिल्ली। (पीआईबी)। केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बहुत उच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने और युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में, नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसको वित्तीय सहायता प्रदान करके और ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करके, नवाचार और कृषि उद्यमीता को बढ़ावा दिया जा सके। ये स्टार्ट-अप्स विभिन्न श्रेणियों जह्यसे कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, मत्स्य पालन आदि में हैं।